नेपालमें अनिश्चय कायम रहनेके आसार !

भारतके पड़ोसी देश नेपालमें राजशाहीकी निरंकुशता कम करनेके लिए वर्षोंतक विभिन्न राजनीतिक दलोंने आन्दोलन किया तब जाकर उसका थोड़ा-सा सार्थक परिणाम सामने आया और नेपाल नरेश महाराजा वीरेन्द्र विक्रम संविधानमें फेरबदल करके थोड़ेसे जनतान्त्रिक अधिकार देनेको तैयार हुए। राजा वीरेन्द्रके नजदीके रुखका एकमात्र कारण था कि आन्दोलनको जनसमर्थन प्राप्त था। उन्होंने सोचा कि जनताको सीधे निर्वाचनका अधिकार मिल जाना काफी है। आज यह साबित हो गया कि नेपाल नरेशका सोचना बिल्कुल सही था। १९९२ में जनवरीसे मई तक अप्रैलतक लगातार संविधान विशेषज्ञोंकी बैठकें सिर्फ इस बातके लिए होती रहीं कि महाराजाके अधिकारोंमें कमी कैसे की जाय और उनपर अंकुश रखनेके लिए कौनसे प्रावधान किये जाय, लेकिन परिणाम कुछ नहीं निकला और मईमें नेपालकी जनताने नये संविधानके मुताबिक पहली बार जनतान्त्रिक माहौलमें खुलकर मताधिकारका उपभोग किया।

सबसे बड़ी और सुसंघटित पार्टी होनेके कारण नेपाली कांग्रेसकी सरकार बननी स्वाभाविक थी। श्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाने अपने मतदाताओंको यह समझाया कि प्रधान मन्त्रीके रूपमें वे इस स्थितिमें रहेंगे ताकि महाराजा मुख्य बिन्दुओंपर उनकी सलाह माननेको बाध्य हों। उन्होंने नेपालकी जनतासे वायदा किया था कि ऐसी व्यवस्था कायम करनेकी कोशिश की जायगी ताकि लगे कि यहां भी अन्य प्रजातान्त्रिक देशों जैसी स्थिति है पर प्रधान मन्त्री बननेके साथ ही उन्हें लगातार अपनी ही पार्टीके अन्दरूनी मतभेदोंका सामना करना पड़ा गया और अन्ततः उनकी सरकार पांच साल पूरा करनेसे पहले गिर गयी।

मौजूदा स्थितिको देखकर लगता है कि नेपालमें फिरसे अन्दर ही अन्दर पंचायत व्यवस्था कायम होगी, कहनेके लिए भले ही उसे 'त्रिशंकु संसद' कहा जाय। एक ओर जहां राणा पंचोंकी पार्टी राष्ट्रीय प्रजातान्त्रिक पार्टीने २०५ सदस्यीय संसदमें बहुमत साबित करनेके लिए २०३ सीटोंपर अपने उम्मीदवार खड़े किये हैं और राजशाही समर्थक दो पूर्व प्रधान मन्त्री सूर्यबहादुर थापा और लोकेन्द्र बहादुरचन्द बड़े जोशोखरोशके साथ दावा करते हैं कि एक भी सीट उनके हाथसे नहीं निकल पायेगी। त्रिभुवन विश्वविद्यालयके राजनीतिशास्त्र विभागके एक प्रोफेसर (जो अपना नाम नहीं खोलना चाहते) को यह देखकर आश्चर्य हो रहा है कि जिस राष्ट्रीय जनतान्त्रिक पार्टीके १० जुलाईसे पहलेतक ९० सांसद थे, उसे २०३ सीटोंपर अपने उम्मीदवार खड़े करनेकी हिम्मत कहांसे आ गयी। सिर्फ तीन वर्षमें कौन-सा करिश्मा हो गया कि इस पार्टीका इतना व्यापक जनाधार तैयार हो गया। ये बताते हैं कि १९९२ में चुनाव होनेके समयतक तीन बातोंको लेकर जिच बरकरार रह गयी थी- पहला था कि नेपाली सुप्रीम कोर्टके मुख्य न्यायाधीश और नेपालकी तीनों सेनाओंके अध्यक्षकी नियुक्तिमें महाराज प्रधान मन्त्रीकी सलाह माननेको बाध्य हैं या नहीं। दूसरा कि आपातस्थिति किन हालातोंमें घोषित की जा सकती है और उस दौरान वास्तविक शक्तियां प्रधान मन्त्रीके हाथमें केन्द्रित होंगी या महाराजाके हाथमें। वैसे पूरे नेपालमें सभी जानते हैं कि इन मामलोंमें महाराजाकी इच्छा ही सर्वोपरि होगी, लेकिन थोड़े जागरूक मतदाता यह जानना चाहते थे कि प्रधान मन्त्री और महाराजाकी क्या बातचीत होती है। लोगोंको बताया गया था कि बहुमतसे चुनकर आनेवाली सरकारके प्रधान मन्त्री, संविधान विशेषज्ञ और महाराजा आपसमें विचार-विमर्श करके सब कुछ तय कर लेंगे। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि जब-जब निश्चित तारीख तय करनेकी बात चली, प्रधान मन्त्री स्वयं संकटमें फंस गये। पहले सरकार बचायें कि पहले बातचीत करें।

नेपाली जनताको बड़ी उम्मीदें थीं, मतदाता सोचते थे कि आधा फासला तय कर चुके, बाकी हमारी सरकार पांच सालमें कर लेगी। यही वजह है कि जनता आम चुनावके लिए तैयार नहीं थी। भारतीय मूलके मधेसियोंकी सबसे बड़ी पार्टी नेपाल सद्भावना पार्टीके अध्यक्ष गजेन्द्रनारायण सिंह काफी विस्तारसे इस सम्बन्धमें चर्चा करते हैं। उनका कहना है कि १५ नवम्बरका चुनाव नेपालकी जनतापर थोपा गया है क्योंकि मतदाता इसके लिए कतई तैयार नहीं थे। तब भी रुचि लेते, अगर मतदाताओंके पास ऐसी किसी पार्टीका विकल्प होता जो सरकार बना सकती। सबसे बड़ी पार्टी नेपाली कांग्रेसकी इस चुनावमें सबसे बुरी गत हो रही है। १० जुलाईको प्रधान मन्त्री कोइरालाकी सरकार गिरानेके लिए जिम्मेदार उनकी पार्टीके ३६ सांसद चुनाव मैदानमें हैं और उनका सीधा मुकाबला अपनी ही पार्टीके प्रतिद्वन्द्वियोंसे है।

श्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाके बारेमें चर्चा है कि वे अपने तीन वर्षोंके कार्यकालमें राजदरबारके हिमायती रहे। उनके सम्बन्धमें एक रिपोर्ट यह भी है (फार ईस्टर्न इकनॉमिक रिव्यू) कि जल्दबाजीमें संसद भंग करनेकी सिफारिश करना और फिर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा महाराजाके कदमको उचित ठहराना एक सुनियोजित योजनाके तहत हुआ है जिसमें श्री कोइराला भी शामिल हैं और अब श्री कोइराला और नेपाली कांग्रेसके दूसरे वरिष्ठ नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई दोनोंने अपने-अपने समर्थकोंको एक-दूसरेके खिलाफ चुनाव मैदानमें उतारा है जो इस पार्टीके लिए आत्मघाती होगा। वामपन्थी पार्टियोंपर भी सशक्त विपक्षकी भूमिका न निभा पानेका आरोप नेपाल सद्भावना पार्टीके नेता श्री गजेन्द्रनारायण सिंह लगाते हैं। कई जगह संयुक्त जनमोर्चाके कार्यकर्ता नेपाली कांग्रेसके बागी प्रत्याशियोंके लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। दूसरी तरफ राजशाही समर्थक राष्ट्रीय प्रजातान्त्रिक पार्टीके नेताओंके हौसले बुलन्द हैं। उन्हें किसी भी पार्टीसे ज्यादा सीट हासिल करनेका दावा है, लेकिन यह भी मानकर चल रहे हैं कि उनकी पार्टी बहुमत नहीं साबित कर पायेगी।

नेपाल सद्भावना पार्टीका मामला अन्य पार्टियोंसे थोड़ा अलग-थलग है क्योंकि यह सिर्फ भारतीय मूलके मधेसियोंका प्रतिनिधित्व करती है जबकि अन्य पार्टियां पहाड़ियोंकी हैं जिनका मधेसियोंके प्रति उपेक्षापूर्ण रवैया रहा है। श्री गजेन्द्रनारायण सिंहका आरोप है कि मधेसियोंके साथ पिछले कई वर्षोंसे सरकारका सौतेला व्यवहार चल रहा है। मधेसियोंको दूसरे दर्जेकी नागरिकता दी गयी है और इन्हें विश्वसनीय नहीं माना जाता, इसलिए इस बिरादरीके लोगोंको सेना तथा पुलिसमें ऊंचे पदोंपर नहीं लिया जाता। नेपालकी कुल आबादीके आधेमें मधेसिया आते हैं और जब आबादीके हिसाबसे नेपाली मूलके लोगोंके बराबर अधिकारोंकी मांग सद्भावना पार्टीने उठायी तो सरकारकी ओरसे तराईके क्षेत्रोंको काट-काटकर बाहरसे पहाड़ियोंको लाकर बसाया जाने लगा। अबतक तराई क्षेत्रमें २५ लाख नेपाली मूलके पहाड़ियोंको लाकर बसाया जा चुका है जिसका उद्देश्य है मधेसियोंको अल्पमतमें करना क्योंकि इस क्षेत्रमें मधेसियोंकी आबादी ७५ लाखसे भी ज्यादा है।

इतना ही नहीं, अन्य इलाकोंमें जहां हर पांच हजारकी आबादीपर एक चुनाव क्षेत्र है, वहीं तराईमें ४५ हजारकी आबादीपर एक चुनाव क्षेत्र बनाया गया है। ये आरोप है सद्भावना पार्टीके, जिसने इस चुनावमें अपने ८७ उम्मीदवार खड़े किये हैं और श्री सिंहको सभी सीटें जीतनेका पूरा भरोसा है। वे सरकार बनानेकी स्थितिमें आनेका दावा नहीं करते। उन्हें इस बातका बड़ा दुःख है कि सभी पार्टियोंने भारत विरोधको ही अपना मुख्य मुद्दा क्यों बनाया है। उनके नारोंसे और उन नारोंके पीछे चल रही उच्चस्तरीय राजनीतिसे सिर्फ स्वार्थलिप्सा टपकती है। श्री सिंहका कहना है कि जब दार्जिलिंगके गोरखा नेता सुभाष घीसिंगको नेपाल सरकारकी ओरसे मदद दिया जाना यहां लोग उचित ठहराते हैं तो पिछले दिनों जनता दल नेता रामविलास पासवानने अगर कहा कि नेपालमें भी पिछड़ी जातियोंको नौकरियोंमें आरक्षण मिलना चाहिए तो उसमें क्या गलत था।

लोग दबी जुबानसे ये बातें करते हैं लेकिन कोई स्पष्ट बतानेको तैयार नहीं की आखिर इतना बड़ा उलट-फेर हुआ कैसे? श्री मोहनचन्द्र अधिकारी, जिन्हें नेपालका नेल्सन मण्डेला कहा जाता है, के १८ वर्ष कारावासमें गुजारनेका आखिर परिणाम क्या निकला। श्री सिंहका कहना है कि मतदाता बेमनसे वोट डालेंगे, क्योंकि वे अच्छी तरह जानते हैं कि परिणाम क्या होना है। वैसे कहनेको न्यायाधीशोंको निर्वाचन अधिकारी बनाया गया है और बाहरसे भी पर्यवेक्षक बुलाये गये हैं, लेकिन कोई पार्टी अकेली तो क्या मिलजुलकर भी सरकार नहीं बना पायेगी। वास्तवमें सरकार बनानेकी फिक्र किसीको है भी नहीं। ये पार्टियां इस पक्षमें जरूर हैं कि भारतसे जितना सम्भव हो लाभ ले लिया जाय, लेकिन नेपालकी नदियोंसे भारतको कोई फायदा न उठाने दिया जाय। हिन्दीको दूसरी राजभाषाका दर्जा देनेकी सद्भावना पार्टीकी मांग उन्हें अनर्गल लगती है और यह भूल जाते हैं कि तराईकी उपजाऊ जमीन नेपालकी अर्थव्यवस्थाकी जड़ है। श्री सिंहके मुताबिक चीनसे चोरी-छिपे हथियार लेनेके पीछे भारत विरोधी रुखके अलावे और कुछ नहीं है। वे जनतन्त्रके गर्तमें जा रहे हैं भविष्यको लेकर चिन्तित हैं।

-शशिधर खां

अन्तरराष्ट्रीय

मतदाता बेमनसे वोट डालेंगे, क्योंकि वे अच्छी तरह जानते हैं कि परिणाम क्या होना है। वैसे कहनेको न्यायाधीशोंको निर्वाचन अधिकारी बनाया गया है और बाहरसे भी पर्यवेक्षक बुलाये गये हैं, लेकिन कोई पार्टी अकेली तो क्या मिलजुलकर भी सरकार नहीं बना पायेगी। वास्तवमें सरकार बनानेकी फिक्र किसीको है भी नहीं।